ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 77-81**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

भारतीय कृषि पर शहरीकरण और उसका प्रभाव

डॉ0 पूनम गुप्ता

असिस्टेंट प्रोफेसर– भूगोल विभाग, सतीश चन्द्र कॉलेज, बलिया (उ0प्र0) भारत

Received-19.09.2025, Revised-26.09.2025, Accepted-02.10.2025 E-mail: poonamsccollege@gmail.com

***सारांशः** भारत में शहरीकरण विकासशील देशों में पाए जाने वाले अधिकांश विशिष्ट लक्षणों को साझा करता है और यह विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा होने के नाते कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग और सेवा–प्रधान शहरी अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत में तेज़ी से बढ़ रहा शहरीकरण आर्थिक विकास का संकेत है, लेकिन इसका कृषि क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि में कमी, ग्रामीण श्रम बल का पलायन, जल संसाधनों पर दबाव, और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नए संकट उत्पन्न हो रहे हैं। शहरीकरण, पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की ओर रूपांतरण तथा जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में प्रगतिशील संकेन्द्रण का एक सूचकांक है। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की मात्र 2.4 प्रतिशत सतहकृ135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटरकृपर स्थित है। यह भूमि परिवर्तन का शायद सबसे नाटकीय और अपरिवर्तनीय स्वरूप है। पिछले शताब्दी में विश्व ने जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है, जिसमें पिछले तीन दशकों के दौरान हर दशक लगभग एक अरब लोगों की वृद्धि हुई। भारत में, स्वतंत्रता के पूरे काल में शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ी है। भारत ने एशिया के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों के विकास पैटर्न को साझा किया है। देश ने पिछले कुछ वर्षों में लगभग 8% जीडीपी वृद्धि देखी है और भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। शहरीकरण को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। भारत शहरीकरण की प्रक्रिया के तीव्र गति वाले चरण में है।*

इस विश्लेषण के लिए भारत के 16 प्रमुख कृषि राज्यों को 1981 से 2016 की अवधि हेतु विचार किया गया है, जिसके लिए मुख्यतः भारत की जनगणना और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से डेटा लिया गया है। प्रायोगिक अनुमानों से पता चलता है कि जीडीपी में कृषि के उच्च हिस्से, खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल, तथा ग्रामीण पुरुष कृषि रोजगार का शहरीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर, उर्वरक के अधिक उपयोग, कृषि पर राज्य सरकार के व्यय, प्रमुख फसलों (गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा) के उत्पादन, ग्रामीण महिला कृषि रोजगार, तथा ग्रामीण साक्षरता दर का शहरीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि कृषि उत्पादकता का प्रभाव शहरीकरण पर सकारात्मक है। यह शोध पत्र यह अध्ययन करता है कि भारत में शहरीकरण का पैटर्न बड़े शहरों में जनसंख्या और गतिविधियों के निरंतर संकेन्द्रण द्वारा चिह्नित है।

***कुंजीभूत शब्द–** भारतीय कृषि, शहरीकरण, ग्रामीण साक्षरता, कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था, औद्योगीकरण, कृषि रोजगार, प्रभाव।*

परिचय– कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि यह रोजगार तथा जीविका में अत्यधिक योगदान देती है, यद्यपि इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान अपेक्षाकृत कम हो गया है। ग्रामीण भारत न केवल अपनी जनसंख्या वृद्धि दर और कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी में गिरावट से गुजर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय ळक्ष में अपने योगदान में भी कमी का अनुभव कर रहा है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सीमित शहरी GDP आँकड़े दर्शाते हैं कि कुल GDP में शहरी क्षेत्र के योगदान का हिस्सा समय के साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है–1970–71 में 38% से बढ़कर 2004–05 में 52% तक।

भारत में कृषि क्षेत्र अत्यधिक हद तक मानसून पर निर्भर है, जो अक्सर अस्थिर रहता है; इसलिए इस क्षेत्र में प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। कृषि में रोजगार अवसरों की कमी और निम्न उत्पादकता स्तर, कुल GDP में कृषि क्षेत्र के घटते योगदान के प्रमुख कारण हैं। इसी तर्क पर यह भी समझा जा सकता है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान ने भी ळक्ष में कृषि हिस्सेदारी में गिरावट को बढ़ावा दिया है।

भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जहाँ कृषि अभी भी लगभग 42% कार्यबल को रोजगार देता है। 2011 से 2025 के बीच भारतीय शहरी आबादी में 30% से बढ़कर लगभग 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। शहरीकरण के कारण भूमि उपयोग पैटर्न, श्रम संरचना, बाजार तंत्र और कृषि तकनीक में परिवर्तन आ रहे हैं। यह शोध पत्र इन्हीं परिवर्तनों की गहन समीक्षा प्रस्तुत करता है। शहरीकरण पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से आधुनिक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्थाओं की ओर रूपांतरण तथा जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में संकेन्द्रण का एक सूचक है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन का शायद सबसे नाटकीय और अपरिवर्तनीय रूप है। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होने और गैर–कृषि विकास का शहरी आय पर अधिक प्रभाव होने के कारण, प्रवासन और प्रेषण (remittance) के माध्यम से शहरी अवसरों तक पहुँच आय प्रसार का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है।

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। शहरी उपयोग हेतु भूमि का विस्तार लगातार बढ़ रहा है, हालाँकि इसका कुल फसल उत्पादन पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण और बढ़ती क्रय शक्ति ने खाद्य उपभोग पैटर्न में भी परिवर्तन किए हैं। महँगे पशु–आधारित उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। कृषि आधुनिकीकरण, वाणिज्यीकरण, गैर–कृषि वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती मांग, शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता तथा कल्याणकारी नीतिगत हस्तक्षेप जैसे कारकों ने श्रम शक्ति को कृषि से हटाकर अधिक लाभकारी गैर–कृषि गतिविधियों की ओर आकर्षित किया है। अतः कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना हुआ है, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा का भी आधार है। शहरीकरण और आर्थिक विकास व्यापक रूप से एक–दूसरे के पूरक हैं; इसलिए कृषि उत्पादन के मुद्दे को आय में निरंतर वृद्धि और शहरीकरण की नवीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में समझना आवश्यक है। अतः इस शोध पत्र में भारत में शहरीकरण और कृषि वृद्धि के मध्य संबंध का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

साहित्य पुनरावलोकन– अंकिता राठी (2011) ने अपने शोध पत्र "सीइंग द अर्बन फ्रॉम द एग्रीरियनः इमरजिंग फॉर्म्स ऑफ़ एग्रीरियन अर्बनाइजेशन इन इंडिया" में ग्रामीण व कृषि आधारित संदर्भ से शहरीकरण को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। पारंपरिक तौर पर शहरीकरण को अधिकतर शहरों की विस्तारवादी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जबकि लेखक दिखाती हैं कि भारत में शहरीकरण ग्रामीण और कृषि सम्बंधी सामाजिक आर्थिक बदलावों के साथ गहरे ढंग से जुड़ा हुआ है। यानी शहरी नहीं केवल शहरों से विकसित होता, बल्कि वह ग्रामीण कृषि परिदृश्य से भी जन्म लेता है। लेख में "Agrarian Urbanism" यानी कृषि आधारित शहरीकरण की अवधारणा को प्रमुखता दी गई है, जो बताती है कि शहरीकरण ग्रामीण भूमि, श्रम, जाति संबंध और कृषि बाज़ार से गहरे रूप से प्रभावित होता है। शोध में पंजाब के छोटे शहर पात्रण को केस स्टडी के रूप में लिया गया है, जहाँ यह दिखाया गया है कि कैसे ऐतिहासिक कृषि परिवर्तन, भूमि अधिकार, जाति संबंध और कृषि नीतियों ने व्यवसाय, व्यापार और शहरी संरचनाओं को विकसित किया है। लेखक सुझाव देता है कि शहरीकरण ग्रामीण को खत्म नहीं करता, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों को एक साथ विकसित तथा सह निर्मित करता है। शहरी परिवर्तन ग्रामीण कृषि संबंधों और सामाजिक ढांचों के साथ जुड़े रहते हैं। कृषि के इतिहास, भूमि निवेश, श्रम संबंध और जाति आधारित सामाजिक असमानताएँ शहरी बदलाव को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारतेंदु पांडे और कैरेन सी. सेटो (2015) ने अपने शोध पत्र "अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल लैंड लॉस इन इंडियाः कम्पेरिंग सैटेलाइट एस्टिमेट्स विद सेनस डेटा" में 2001 से 2010 के बीच भारत में शहरीकरण के कारण कृषि भूमि हानि का विश्लेषण किया है। शोध में सैटेलाइट (MODIS) डेटा और कृषि जनगणना डेटा दोनों का उपयोग कर भूमि उपयोग परिवर्तन की पहचान की गई है कृ विशेष रूप से कृषि भूमि का शहरी विस्तार में परिवर्तन। कृषि भूमि का शहरीकरण में परिवर्तन अधिकतर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ छोटे शहरों के पास कृषि भूमि है, न कि केवल बड़े महानगरों में। 2001–2010 के दौरान प्रत्येक राज्य ने अपनी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% से भी कम हिस्सा कृषि भूमि के शहरी उपयोग में खोया, लेकिन यह हानि 2006 के बाद लगातार बढ़ती गई। कृषि भूमि का नुकसान उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे कम रहा, जबकि औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि वाले राज्यों/जिलों में यह अधिक प्रचलित रहा। व्यापक रूप से देखा जाए तो कृषि भूमि का नुकसान कुछ विशिष्ट राज्यों और जिलों में केंद्रित है, न कि पूरे देश में समान रूप से। लेख में बताया गया है कि शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि का संक्रमण अभी तक कुल भू क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या और विस्तार बढ़ता है, कृषि भूमि की कमी और भूमि उपयोग संघर्ष बढ़ने की संभावनाएँ हैं।

अभिजीत एस. मारावर (2016) ने अपने शोध पत्र "अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड" में तेज़ शहरीकरण और आबादी में वृद्धि के कारण कृषि भूमि पर भारी दबाव पड़ रहा है। शहरी विस्तार के लिए भूमि की माँग बढ़ने से कृषि भूमि का उपयोग बदलकर आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा नागरिक उपयोग में हो रहा है। इससे कृषि योग्य भूमि कम हो रही है और किसानों के पास खेती के लिए कम जमीन बच रही है। लेख में बताया गया है कि भूमि की आपूर्ति स्थिर होती है कृ यानी भूमि की मात्रा बढ़ती नहीं है, जबकि आबादी और शहरों की जरूरतें बढ़ती रहती हैं। इसका नतीजा यह है कि कृषि भूमि का काफी हिस्सा शहरों के विकास के लिए खो जाता है। इससे कृषि उत्पादन में कमी, आजीविका पर प्रभाव, भोजन सुरक्षा की समस्याएँ, तथा स्थानीय किसानों की आजीविका में गिरावट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

सीमा पुरुषोथमण और शीतल पाटिल (2019) अपने पुस्तक "अग्ररियन चेंज एंड अर्बनाइजेसन इन साउथर्न इंडियाः सिटी एंड थे पिजेंट" में दक्षिण भारत में कृषि परिवर्तनों और शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। लेखक, सीमा पुरुषोथमण और शीतल पाटिल, मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे शहरी विस्तार और नगरीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और कृषि परंपराओं को प्रभावित किया है। पुस्तक में दिखाया गया है कि दक्षिण भारत में कृषि केवल उत्पादन का साधन नहीं रह गई है, बल्कि शहरीकरण, भूमि परिवर्तन और बाजार पर निर्भरता के कारण सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी बदलाव आया है। किसान अब पारंपरिक खेती पर कम निर्भर हैं और अधिकतर भूमि बेचने, किराये पर देने या शहरी विकास परियोजनाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहे हैं।

शहरीकरण का प्रभाव– भूमि उपयोग में बदलावः कृषि भूमि धीरे धीरे औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित हो रही है।

सामाजिक प्रभावः ग्रामीण समुदायों में रोजगार और आजीविका के नए अवसर तो आए हैं, लेकिन साथ ही पारंपरिक कृषि समुदाय कमजोर हो रहे हैं। लेखक बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच पारंपरिक सीमाएं अब धुंधली हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र केवल भोजन या कच्चे माल का स्रोत नहीं रहे, बल्कि शहरी विकास का हिस्सा बन गए हैं।

शोध के उद्देश्य–

1. भारत में शहरीकरण की गति और स्वरूप को समझना।
2. कृषि भूमि, उत्पादन और संसाधनों पर शहरीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सामाजिक–आर्थिक परिणामों का अध्ययन करना।
4. कृषि आधुनिकीकरण, वाणिज्यीकरण, गैर–कृषि वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती मांग इत्यादि को समझाना।

शोध पद्धति– शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक तथ्यों पर आधारित अध्ययन है, इसके लिए विभिन्न शोध पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों, तथा इंटरनेट आधारित सूचनाओं का अध्ययन किया गया हैं। यह पेपर मूल रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि– भारतीय कृषि ने पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है, विशेषकर 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति प्रौद्योगिकी को अपनाने के बाद। इस तकनीक में उत्पादकता बढ़ाने की विशाल क्षमता थी, जिससे उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जहाँ इसे लागू किया गया। चूँकि हरित क्रांति का प्रसार कुछ विशेष राज्यों और क्षेत्रों के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ था, इसलिए चयनित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में उच्च वृद्धि दर्ज हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों को कृषि उत्पादन में ठहराव या कम वृद्धि का सामना करना पड़ा।

कृषि विकास के प्रदर्शन को व्यापक रूप से कुछ प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला चरण, जो मध्य 1960 के दशक तक की अवधि को कवर करता है और प्री–ग्रीन रेवोल्यूशन अवधि के रूप में जाना जाता है, क्षेत्र विस्तार के माध्यम से प्राप्त वृद्धि से चिह्नित था। सभी फसलों के कृषि उत्पादन में 3.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें क्षेत्र वृद्धि दर 1.58 प्रतिशत तथा उत्पादकता वृद्धि दर 1.21 प्रतिशत थी। यद्यपि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुईं, फिर भी

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

विशेषकर 1961 से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहीं था। खाद्यान्न आयात 1961 में 3.5 मिलियन टन से बढ़कर 1966 में 10.36 मिलियन टन हो गया। खेती के लिए अतिरिक्त भूमि लाने की संभावनाएँ सीमित थीं, इसलिए निकट भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजना आवश्यक महसूस हुआ। मध्य साठ के दशक में लगातार दो वर्षों की सूखे की स्थिति ने परिस्थितियों को और खराब कर दिया।

इसके जवाब में, उच्च उपज वाली किस्मों (गेहूँ और चावल) के बीजों को अपनाकर तथा सिंचाई वाली परिस्थितियों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से हरित क्रांति शुरू की गई। इस चरण में देश ने खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। इस अवधि की वृद्धि मुख्यतः उत्पादकता–आधारित वृद्धि थी। हालाँकि, तकनीकी परिवर्तनों के नकारात्मक बाह्य प्रभाव विभिन्न रूपों में सामने आने लगे। 1990 का दशक कृषि क्षेत्र के लिए मिश्रित प्रदर्शन वाला रहा। प्रारंभ में कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि के संकेत दिखाए, लेकिन जल्द ही अंतः–क्षेत्रीय विकास दबावों के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की प्रवृत्ति में मंदी के संकेत दिखाई देने लगे।

भारत में शहरीकरण– भारत में स्वतंत्रता के बाद पूरे कालखंड में शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप शहरी जनसंख्या का हिस्सा 1951 में 17.29 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में लगभग 28 प्रतिशत हो गया। लेकिन शहरी हिस्सेदारी में वृद्धि की दर केवल लगभग एक प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है, और यह दर 1980 तथा 1990 के दशकों में वास्तव में धीमी हो गई। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल 102.87 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 28.61 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में और 74.25 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 1901 में कुल जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जो 2001 में बढ़कर 102.87 करोड़ हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 1901 में 2.59 करोड़ से बढ़कर 2001 में 28.61 करोड़ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। शहरी जनसंख्या 31.16 करोड़ (26.3%) थी। ग्रामीण जनसंख्या 89.1 करोड़ (68.8%) थी। यह शहरीकरण की क्रमिक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बावजूद, शहरीकरण का प्रभाव भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण रहा है, खासकर रोजगार, अवसंरचना, और शहरी जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में। इस अवधि में शहरीकरण के साथ–साथ भारत में कई प्रमुख बदलाव आए हैं जैसे कि औद्योगिकीकरण, ग्रामीण–शहरी प्रवास, और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का विस्तार।

स्वतंत्रता के समय देश की जनसंख्या 34.2 करोड़ थी। 1951 से 2001 के पाँच दशकों में भारत की जनसंख्या लगभग तीन गुना हो गई। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरें अनियमित रही हैंकृ1951 में 13.31 प्रतिशत से बढ़कर 1971 में 24.8 प्रतिशत हो गईं, और उसके बाद 1981 में 24.7 प्रतिशत, 1991 में 23.9 प्रतिशत तथा 2001 में 21.5 प्रतिशत पर आ गईं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई। इस दशक (2001–2011) के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर घटकर लगभग 17.7 प्रतिशत रह गई, जो यह दर्शाती है कि भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।

शहरीकरण के संदर्भ में, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 37.7 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 31.16 प्रतिशत थी। शहरी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी बड़े शहरों में केंद्रित है।लगभग 65 प्रतिशत शहरी जनसंख्या वर्ग–I (Class I) शहरों में निवास करती है, जबकि इन शहरों की संख्या कुल शहरों का केवल लगभग 10 प्रतिशत है। इससे शहरी जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण स्पष्ट होता है। शहरों का विकास मुख्यतः शहरी आकर्षण कारकों (Urban Pull Factors)– जैसे रोजगार के अवसर, औद्योगिकीकरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन सुविधाओं के कारण होता है। इसके साथ ही ग्रामीण धक्का कारक (Rural Push Factors), जैसे कृषि पर बढ़ता दबाव, बेरोजगारी, भूमि की कमी और गरीबी, लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित करते हैं।

इस प्रकार, 2011 की जनगणना के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो रही है, जबकि शहरीकरण की प्रक्रिया निरंतर, यद्यपि क्रमिक, रूप से आगे बढ़ रही है।

शहरीकरण और उसकी समस्याएँ– शहरीकरण की परिभाषा किसी देश की वह प्रक्रिया है जिसमें उसकी जनसंख्या का बढ़ता हुआ हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहने लगता है (और परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला हिस्सा कम होता जाता है)। अधिकांश शहरीकरण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में निवल प्रवास का परिणाम होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्राकृतिक वृद्धि दरों में अंतर भी शहरीकरण को प्रभावित करता है, हालांकि सामान्यतः ये अंतर शहरीकरण को कम करते हैं। शहरीकरण शब्द का उपयोग शहरी भूमि–उपयोग के विस्तार के लिए भी किया जाता है। इसके विपरीत, शहरी भूमि–उपयोग का बहुत–सा विस्तार घनी बस्तियों से अधिक फैलाव वाली बस्तियों की ओर बदलाव का परिणाम होता है। वास्तव में, शहरीकरण शब्द का उपयोग दो विपरीत प्रकार के स्थानिक परिवर्तनों के लिए किया जा रहा है, जिनका उदाहरण के लिए कृषि हेतु उपलब्ध भूमि पर विपरीत प्रभाव हो सकता है।

कई विकास विशेषज्ञ शहरीकरण को एक समस्या के रूप में देखते हैं। फिर भी, कोई भी राष्ट्र शहरीकरण के बिना समृद्ध नहीं हुआ है और कोई भी समृद्ध राष्ट्र ऐसा नहीं है, जो मुख्यतः शहरी न हो। पिछले 60 वर्षों में आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण के बीच एक मजबूत संबंध देखा गया है, और विश्व के अधिकांश गरीब राष्ट्र अब भी सबसे कम शहरीकृत देशों में शामिल हैं। शहरी क्षेत्र जीवन–स्तर में सुधार के लिए अनेक संभावित लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था और निकटता उपलब्ध होती है। पिछले दो शताब्दियों में शहरीकरण का संबंध गरीब–हितैषी सामाजिक सुधारों से भी रहा है, जिनमें शहरी गरीबों के सामूहिक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अनेक शहरी क्षेत्रों में अभी भी गंभीर विकास संबंधी समस्याएँ मौजूद हैं, जिनमें शहरी गरीबी का उच्च स्तर, खाद्य सुरक्षा की समस्याएँ, तथा शिशु और बाल मृत्यु दर की गंभीर स्थिति शामिल हैं।

इसके परिणाम अधिकांश शहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैंः अर्थात् बड़ी आबादी बहुत खराब और अत्यधिक भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में अनौपचारिक बस्तियों या झुग्गी–झोपड़ियों में रहती है, जहाँ जल, स्वच्छता, जल निकासी, स्वास्थ्य सेवाएँ, विद्यालय और कानून–व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान नहीं होता। यह स्थिति उन शहरों में भी देखी जाती है जहाँ बहुत तेज आर्थिक विकास हुआ है। यहाँ कुपोषण, शिक्षा की कमी, शोषण की गंभीर समस्याएँ, तथा महिलाओं के विरुद्ध जीवन के लगभग सभी पहलुओं में गहरी जड़ें जमाए भेदभाव जैसी समस्याएँ मौजूद रहती हैं।

निष्कर्ष– भारत में जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों का निरंतर संकेन्द्रण बड़े शहरों में दिखाई देता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की भारी मात्रा में होने वाली जनसंख्या गतिशीलता के परिणामस्वरूप भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शहरी उपयोग के लिए परिवर्तित होने वाली भूमि लगातार बढ़ रही है, यद्यपि इसका कुल फसल उत्पादन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए,

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की सतत वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए, शहरीकरण और आर्थिक विकास की प्रक्रियाएँ अपरिवर्तनीय होंगी, और यह विश्लेषण आवश्यक है कि कृषि उत्पादन ऐसे परिवर्तनों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देगा।

पिछले पाँच दशकों में भारतीय कृषि ने महत्वपूर्ण उतारदृचढ़ाव देखे हैंकृकहीं उल्लेखनीय वृद्धि के चरण रहे, तो कहीं ठहराव के दौर। लेकिन समय के साथ देश chronic hunger (पुरानी भूख) और आयात पर निर्भरता की स्थिति से बाहर निकलकर खाद्यान्न उपलब्धता में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सफल रहा है। शहरी जनसंख्या में तेज़ वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास का परिणाम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान–प्रदान ग्रामीणदृशहरी संपर्क का एक महत्वपूर्ण घटक है। शहरीकरण उच्च–मूल्य वाली वस्तुओं की मांग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। वर्ष 2025 तक शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है। इससे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की मांग में तीव्र वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में गरीबी और जनसंख्या वृद्धि को प्रतिस्थापन स्तर से नीचे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही, जब तक कृषि विकास, शहरी नियोजन, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विकास और संसाधन प्रबंधन में पर्यावरणीय चिंताओं को गंभीरता से शामिल नहीं किया जाता, स्थिति भविष्य में और अधिक गंभीर हो सकती है।

अन्ततः, यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था से शहरी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि यह विकास का महत्वपूर्ण चरण है। कृषि का शहरीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत में उच्च शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। भारत का शहरीकरण आर्थिक विकास पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि, भारत के समग्र विकास के लिए सुनियोजित शहरीकरण और सुदृढ़ कृषि विकास नीति की आवश्यकता है।

सुझाव एवं समाधान– शहरीकरण ने भारत में कृषि क्षेत्र पर कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाले हैं। भूमि की कमी, जल संकट, श्रम बल की कमी और पारंपरिक कृषि प्रणालियों में परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इन प्रभावों से निपटने और कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव और समाधान महत्वपूर्ण हैं:

1. शहरी विस्तार के दबाव से कृषि भूमि तेजी से सिकुड़ रही है। इसे रोकने के लिए कृषि भूमि को केवल अत्यावश्यक सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहित किया जाए तथा भूमि उपयोग के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम लागू हों।
2. शहरों के विकास में कृषि और पर्यावरणीय क्षेत्र का समावेश आवश्यक है। इसके लिए शहरों के आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए।
3. शहरी कृषि (अर्बन एग्रीकल्चर) जैसे छतों पर खेती, सामुदायिक बाग, वर्टिकल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए।
4. नगर निगम खेती के लिए विशेष अर्बन फार्मिंग जोन निर्धारित करें तथा किसानों को शहरी क्षेत्रों में खेती जारी रखने हेतु अनुदान या सब्सिडी दी जाए।
5. शहरीकरण ने कृषि जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा दिया है। इसे कम करने के उपाय वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) के लिए तालाब, चेक–डैम और नहरें बनाना।
6. सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देना एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण।
7. शहरीकरण के कारण ग्रामीण युवाओं का पलायन बढ़ा है। इसे रोकने के उपाय गाँवों में एग्रो–प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना तथा पारंपरिक रोजगार जैसे हस्तशिल्प, खादी, डेयरी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
8. कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी पर प्रशिक्षण देना।
9. सरकारी योजनाएँ जैसे– PM & Kisan, MSP, FPO नीति, और PMFBY बीमा योजना का पारदर्शी और समय पर कार्यान्वयन।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राकेश, रेणु. (2021). जल जीवन मिशन. योजना, 65(4), अप्रैल।
2. सिंह, धीरज (2020). जल और स्वच्छता, कुरुक्षेत्र, वर्ष 66(12), अक्तूबर।
3. सिंह, सविंद्र (2017). पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. पाठक, गणेश कुमार (2004). जल संसाधन, उपयोग दुरुपयोग एवं बचाव, जिज्ञासा, 18 ।
5. दत्त, आर., एवं महाजन, अ. (2018). भारतीय अर्थव्यवस्था. एस. चाँद एंड कंपनी।
6. खोसला, ए. एन. (2010). भारत का आर्थिक भूगोल. के. एन. पब्लिशर्स।
8. Marawar S. Abhijit (2004) Urbanization and Its Impact on Agricultural Land, IJRCEAD.
9. Purushothaman, S., & Patil, S. (2019), Agrarian change and urbanization in Southern India: City and the peasant. Springer.
10. Pandey, B. (2015). Urbanization and agricultural land loss in India: Comparing satellite estimates with census data. Journal of Environmental Management, 159, 258–268.
11. Rathi, A. (2021). Seeing the urban from the agrarian: Emerging forms of agrarian urbanization in India. Sociologies / Sociologies, 12.
12. Misra, R. P., / Sundaram, K. V. (2013). Urbanization and agricultural development in India. Oxford University Press.
13. Kundu, A. (2011). Urbanisation and migration: An analysis of trends, patterns and policies in Asia. Human Development Research Paper.
14. Bhalla, G. S., /Singh, G. (2010)- Indian agriculture: Four decades of development. Sage Publications, Chand, R., Raju, S. S./Pandey, L. M. (2011). Urbanization, migration and agricultural growth in India. National Centre for Agricultural Economics and Policy Research.

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

15. Ghosh, J. (2010). Globalization, export&oriented employment for women and social policy. Oxford University Press.
16. Kumar, P., /Mittal, S. (2006)., Agricultural productivity trends in India: Sustainability issues. Agricultural Economics Research Review, 19(2), 71–88.
17. Government of India. (2020). Agricultural statistics at a glance. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
18. Census of India. (2011). Rural–urban distribution of population in India. Government of India.

*****